शिक्षक - रवि शंकर राय विषय - अर्थशास्त्र
दिनांक - 05-08-2020 वर्ग - BA-II

औद्योगिक नीतियाँ

Introduction ⇒ भारत में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था आने से पहले ही कई पश्चिमी अर्थव्यवस्था ने अपने सफल औद्योगिकरण की कहानी दर्ज करा ली थी, जिससे इन देशों में तीव्र वृद्धि एवं विकास हुआ। स्वतंत्र भारत अपनी जीर्ण-शीर्ण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान करना चाहता था। देश के सम्मुख अनेक चुनौतियाँ थी; जैसे व्यापक गरीबी, खाद्यान्न की कमी स्वास्थ्य सुरक्षा इत्यादि जिसपर अधिक ध्यान देना आवश्यक था। अन्य क्षेत्र जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी, वे थे - उद्योग, आधारभूत संरचना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा इत्यादि। 1930 के दशक में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमुख राजनीतिक दल द्वारा निर्णय लिया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का नेतृत्व द्वितीयक क्षेत्र को करना था।

उस समय के सरकार ने यह निर्णय लिया कि अर्थव्यवस्था में सरकार की सक्रिय भूमिका होगी, स्वाभाविक रूप से औद्योगिक क्षेत्र में राज्य का प्रभुत्व कायम रहेगा। सरकारी अधिकृत कंपनियों का विस्तार पूर्ण रूप से होगा। 1990 के दशक के शुरुआत में आर्थिक सुधार द्वारा अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका में मूलभूत परिवर्तन होने के बावजूद भी सरकार के सक्रियता के अवशेष अभी भी दृष्टिगोचर होते हैं। समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीतियों ने ~~...~~ मूलतः अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं संरचना को ~~आका~~ प्रदान किया। यहाँ हमने अभी तक के सरकारी

औद्योगिक नीतियों की एक संक्षिप्त समीक्षा की हैं —

A. 1948 की औद्योगिक नीति
(Industrial policy Resolution, 1948)

इसकी घोषणा 8 अप्रैल 1948 को की गयी। यह न केवल भारत की पहली औद्योगिक नीति का विकास था, बल्कि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप (मिश्रित अर्थव्यवस्था) को भी निश्चित किया। इस नीति के मुख्य अंश निम्नलिखित थे —

1. भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा।

ii) कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को केन्द्र सूची में रखा गया; जैसे - कोयला, पॉवर, रेल, नागरिक, उड्डयन, अस्त्र एवं नागरिक उड्डयन, अस्त्र एवं युद्धोपकरण, रक्षा इत्यादि।

iii) कुछ अन्य उद्योगों (सामान्यतः मध्य वर्ग) को राज्य सूची में रखा गया; जैसे कागज, औषधि, कपड़ा, साइकिल, रिक्सा, दो पहियों वाले वाहन इत्यादि।

iv) अन्य उद्योग को (जो केन्द्र और राज्य सूची में नहीं थे) निजी क्षेत्र के निवेश के लिए रखा गया, जिसमें कई के लिए अनिवार्य अनुज्ञापन (Compulsory Licensing) का प्रावधान था।

v) 10 वर्ष उपरांत नीति की समीक्षा।

B. 1956 की औद्योगिक नीति
(Industrial policy Resolution, 1956)

1948 की औद्योगिक नीति के परिणामों से प्रोत्साहित होकर आठ वर्षों बाद भारतीय उद्योग के लिए नई तथा अधिक ठोस नीति की घोषणा की गयी — 1956 के नई औद्योगिक नीति के निम्नलिखित मुख्य प्रावधान थे —

1. उद्योगों का आरक्षण

उद्योगो का तीन अनुसूची में वर्गीकरण जिसे उद्योगो का आरक्षण भी कहते है —

* अनुसूची - A

इस अनुसूची में 17 औद्योगिक क्षेत्र थे, जिसपर केन्द्र का सम्पूर्ण अधिकार था। इस प्रावधान के अन्तर्गत स्थापित उद्यम को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSUs) कहते थे, जो बाद में PSUs (सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) के नाम से प्रसिद्ध हुए। यद्यपि उद्योगो की संख्या मात्र 17 है। तथापि भारत सरकार द्वारा स्थापित सर्वाजनिक क्षेत्र उद्यमों (PSUs) की संख्या वर्ष 1991 तक 254 हो गई थी। इनमें वे औद्योगिक इकाइयाँ भी शामिल हैं जिन्हे सरकार द्वारा 1960 से 1980 के बीच राष्ट्रीयकरण के अभियान द्वारा अधिकृत किया गया।

* अनुसूची - B

इस अनुसूची में 12 औद्योगिक क्षेत्र शामिल थे, जिनमें राज्य सरकार को पहल करना था तथा जिसपर निजी क्षेत्र द्वारा अधिक विस्तृत अनुगामी कार्य किया जाता है। इस अनुसूची में अनिवार्य अनुज्ञापत्र का भी प्रबंध था। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि न तो राज्य तथा न ही निजी क्षेत्र का इन उद्योगों पर एकाधिकार था।

* अनुसूची - C

इनमें वे सभी औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं, जिन्हे अनुसूची A तथा B में शामिल नही किया गया था तथा जिनके तहत निजी उद्यमों को उद्योग स्थापित करने का प्रावधान था। इनमें से कई के लिए अनुज्ञापत्र की व्यवस्था थी तथा उन्हे राज्य